(c) As Indian Iron & Steel Company Limited (IISCO) has been referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), any scheme to be taken up for modernisation of IISCO will have to be in accordance with the orders of the BIFR in this regard. Regarding the present status, SAIL, as advised by the Government, has submitted to the BIFR in the hearing on 18/07/1996 that it would explore the possibility of revival/ modernisation of IISCO through a Joint Venture arrangement, subject to SAIL continuing to retain majority shareholding in the Joint Venture.

Disinvestment of Shares of Public Sector Undertakings

796. SHRI ASHOK MITRA: Wll the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to a study by the Indira Gandhi Institute for Research and Development suggesting that the first three rounds of disinvestment of shares of public undertakings has involved a loss for Government to the extent of Rs. 10,000 crore;

(b) whether any enquiry is proposed to check the veracity of this finding; and

(c) measures proposed to prevent similar losses from disinvestment activities, should these be resumed?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The reference to loss in first three rounds of disinvestment of PSU shares by the Indira Gandhi Institute for Research and Development, Bombay, in their Midyear review of the Economy 1994-95 is not based on a proper appreciation of facts. The matter has been looked into by the Public Accounts Committee of the Parliament.

रोजगार में वृद्धि की दर में कमी

797. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मगंरोला:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989 के बाद से रोजगार में वृद्धि की दर में कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा पंचवर्षीय अंतराल में किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं। रोजगार एवं बेरोजगारी पर एन एस एस ओ का 43वां सर्वेक्षण 1987-88 में आयोजित किया गया एन एस एस ओ द्वारा व्यापक सर्वेक्षण का आगामी 50 वां सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया है, जिसके परिणामों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। एन० एस० एस० ओ० के 50 वें सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने पर ही रोजगार वृद्धि के वर्तमान रूप का पता चल सकेगा।

(ग) आठवीं योजना की कृषि क्षेत्र संबंधी रोजगार नीति में कृषि का तीव्रतर एवं भौगोलिक रूप से विविधीकृत विकास ताकि अब तक के पिछड़े क्षेत्रों में कृषि-विकास संबंधी अधिक अंशदान हो, उच्च स्तर को कृषि का विविधीकरण, अधिक श्रम-गहन फसलें जैसे सब्जी एवं फल विशेषत: उच्च विकसित कृषीय क्षेत्रों में, डेरी, मुर्गी-पालन, मत्स्य पालन एवं कोशकीट पालन जैसे कृषि आधारित तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए आधारभूत संरचना एवं विपणन व्यवस्था का विकास करना, उपज तथा वानिकी हेतु बंजर भूमि के विकास एवं उपयोग हेतु एक विस्तृत कार्य-क्रम सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों हेतु योजनाएं

798. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;